[2013) 5 एस.सी.आर. 1053

महेंद्र नाथ दास

बनाम

भारत संघ और अन्य

{आपराधिक अपील संख्या 2013 की 677}

1 मई, 2013

[जी.एस. सिंघवी और सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, जे.जे.]

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 72- हत्या - अभियुक्त-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई - उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को दया याचिका प्रस्तुत की और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना की - 12 वर्ष के बाद याचिका खारिज कर दी गई - औचित्य - नहीं माना गया - दया याचिका के निपटारे में 12 वर्ष की देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त है - तदनुसार अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया - दण्डादेश - सजा को कम किया जाने का दण्डादेश ।

अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और इस आधार पर मौत की सजा सुनाई गई थी कि उसने एक व्यक्ति की बेहद घृणित और वीभत्स तरीके से हत्या की थी। दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि उच्च न्यायालय और इस न्यायालय ने भी की थी।

इसके बाद, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की और मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना की। 12 साल बाद याचिका खारिज हुई. अपीलकर्ता द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति पर सवाल उठाते हुए दायर की गई रिट याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

त्वरित अपील में जो प्रश्न विचार हेतु उठा था कि क्या संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर दया याचिका के निपटान में 12 साल की देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त थी और उच्च न्यायालय ने उसके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करके एक त्रुटि की थी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए :

अवधारित 1. अपीलकर्ता के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत याचिका प्रस्तुति और अस्वीकृति के बीच 12 वर्ष का समय अंतराल एक लंबा समय था। उसके भारतीय संघ ने इस बार समझाने की कोशिश की है केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच पत्राचार, गृह मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर मामले पर विचार आदि का हवाला देकर समय अंतराल में स्पष्ट किया है। हालांकि, 20.6.2001, के बीच तीन साल के समय अंतराल के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वह तारीख जिस दिन तत्कालीन गृह मंत्री ने अपीलकर्ता द्वारा दायर दया याचिका को अस्वीकार करने की सिफारिश की थी, और सितंबर, 2004, जब फ़ाइल फिर से मंत्रालय के भीतर घूमना शुरू हई और 30.9.2005 के बीच पांच साल

लगे, यानी वह तारीख, जिस दिन राष्ट्रपति ने राय दी कि अपीलकर्ता की दया याचिका स्वीकार की जानी चाहिए और सितंबर, 2010, जब फाइल वास्तव में गृह मंत्रालय द्वारा वापस बुलाई गई थी। इसके अलावा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा तैयार दिनांक 5.10.2010 के नोट में, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. के दिनांक 30.9.2005 के नोट का संदर्भ दिया गया था। 12.10.2010 को राष्ट्रपति कार्यालय में उत्तराधिकारी को अपीलकर्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश करते समय गृह मंत्री ने 30.9.2005 के नोट का उल्लेख तक नहीं किया। राष्ट्रपति के विचारार्थ गृह मंत्रालय द्वारा तैयार सारांश में, जिस पर 18.10.2010 को गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, में भी कोई संदर्भ नहीं दिया गया था तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश एवं नोट दिनांक 30.9.2005 का। ऐसा क्यों किया गया यह उत्तरदाताओं द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका और उसमें दर्ज विभिन्न नोटिंग वाली फ़ाईल राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई होगी, लेकिन उनके विचार के लिए तैयार किए गए सारांश से उनके पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश और दिनांक 30.9.2005 के नोट का उल्लेख करना चूक गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रपति को उनके पूर्ववर्ती द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बारे में अंधेरे में रखा गया और पूरे मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के अवसर से वंचित किया गया। [पैरा 20] [1072 ए-एफ]

1.2. यह न तो प्रतिवादियों का दावा किया गया मामला है और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत की गई है कि भारत

सरकार ने 30.9.2005 को उनके द्वारा दर्ज आदेश की समीक्षा के लिए फाइल तत्कालीन राष्ट्रपति के समक्ष रखी थी, जिनमें द्वारा दिनांक 8.5.2011 को अपीलकर्ता की याचिका पर निर्णय लिया गया कि उसके पूर्ववर्ती के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका के निपटान में राष्ट्रपति को उचित सलाह और सहायता नहीं दी गई थी। [पैरा 21] [1072- जी- एच; 1073- ए]

1.3. उच्च न्यायालय को गृह मंत्रालय द्वारा रखे गए रिकॉर्ड/ फ़ाइलों को देखने का लाभ नहीं मिला और यही कारण है कि आक्षेपित आदेश में 30.9.2005 को राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश और नोट का कोई संदर्भ नहीं है गृह मंत्री के विचारार्थ उनके द्वारा रिकार्ड किया गया। [पैरा 22] [1073- ए- बी]

1.4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता की दया याचिका के निपटारे में 12 साल की देरी मौत की सजा को कम करने के लिए पर्याप्त थी और उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को केवल इस आधार पर खारिज करके गंभीर गलती की कि उसे जघन्य अपराध करने का दोषी पाया गया था। परिणाम में, अपीलकर्ता की दया याचिका को खारिज अवैध घोषित किया जाक़र रद्द किया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे दिये गये मृत्युदण्डादेश की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है, उसे इस न्यायालय ने आजीवन कारावास में बदल दिया है। [पैरा 23,24] [1073- सी- डी; 1075- जी- एच]

दया सिंह बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 61: 1991 (2) एससीआर 462 - लागू माना गया।

महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य (1999) 5 एससीसी 102: 1999 (3) एससीआर 729; जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1973) 1 एससीसी 20: 1973 (2) एससीआर 541; राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी राज्य (1979) 3 एससीसी 464; बचन सिंह बनाम राज्य पंजाब (1980) 2 एससीसी 684; टी. वी. वथीस्वरन बनाम राज्य तमिलनाडु (1983) 2 एससीसी 68; शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 2 एससीसी 344; जावेद अहमद पावला बनाम राज्य महाराष्ट्र (1985) 1 एससीसी 275: 1985 (2) एससीआर 8; महेश वि. म.प्र. राज्य (1987) 3 सेकंड 80: 1987 (2) एससीआर 710; त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य (1989) 1 एससीसी 678: 1989 (1) एससीआर 509; मधु मेहता बनाम भारत संघ (1989) 3 एससीआर 775; सेवक पेरुमल बनाम टी.एन. राज्य (1991) 3 एससीसी 471: 1991 (2) एससीआर 711; धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य। (1994) 2 एससीसी 220: 1994 (1) एससीआर 37; जशुभा भरतसिंह गोहिल बनाम. गुजरात राज्य (1994) 4 एससीसी 353; रावजी बनाम राज्य राजस्थान (1996) 2 एससीसी 175: 1995 (6)आपूर्ति. एससीआर 195; मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुन्ना चौबे (2005) 2 एससीसी 710: 2005 (1) एससीआर 781; स्वामी श्रद्धानंद बनाम राज्य कर्नाटक (2008) 13 एससीसी 767: 2008 (11) एससीआर 93; विवियन रॉड्रिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1971) 1 एससीसी 468: 1971 (3) एससीआर 546; शिवाजी जयसिंह बाबर बनाम महाराष्ट्र राज्य (1991) 4 एससीसी 375; देविंदर पाल सिंह भुल्लर बनाम

राज्य दिल्ली के एन.सी.टी. [निर्णय दिनांक 12 अप्रैल 2013 द्वारा सुप्रीम कोर्ट]; मारू राम बनाम भारत संघ (1981) 1 एससीसी 107; मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470: 1983 (3) एससीआर 413; एडिगा अनम्मा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1974) 4 एससीसी 443: 1974 (3) एससीआर 329 और ईपुरु सुधाकर बनाम। एपी सरकार (2006) 8 एससीसी 161: 2006 (7) पूरक। एससीआर 81 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:

1999 (3) एससीआर 729 पैरा 6 को संदर्भित करता है

1973 (2) एससीआर 541 पैरा 12 को संदर्भित करता है

464 पैरा 12 को संदर्भित किया गया

684' पैरा 12 में संदर्भित

68 पैरा 12 को संदर्भित किया गया

344 पैरा 12 को संदर्भित किया गया

1985 (2) एससीआर 8 पैरा 12 को संदर्भित करता है

1987 (2) एससीआर 710 पैरा 12 को संदर्भित किया गया

1989 (1) एससीआर 509 पैरा 12 को संदर्भित करता है

(1989) 3 एससीआर 775 पैरा 12 को संदर्भित करता है

1991 (2) एससीआर 711 पैरा 12 को संदर्भित करता है

1994 (1) एससीआर 37 पैरा को संदर्भित करता है 12

(1994) 4 पैरा 12 का हवाला दिया गया

1995 (6) पूरक। एससीआर 195 पैरा 12 को संदर्भित करता है

2005 (1) एससीआर 781 पैरा 12 को संदर्भित करता है

2008 (11) एससीआर 93 पैरा 12 को संदर्भित करता है

1971 (3) एससीआर 546 पैरा 13 को संदर्भित करता है

1991 (2) एससीआर 462 को पैरा 13 पर लागू माना गया

375 पैरा 13 को संदर्भित किया गया

101 पैरा 16 का हवाला दिया गया

1983 (3) एससीआर 413 पैरा 16 को संदर्भित करता है

1974 (3) एससीआर 329 पैरा 16 को संदर्भित करता है

2006 (7) पूरक। एससीआर 81 पैरा 16 को संदर्भित करता है

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 2013 की संख्या 677

श्याम दीवान, पी.एस. सुधीर, अविजीत रॉय, टी.ए. खान, उपस्थित पक्षकारों के लिए

न्यायालय का निर्णय जी.एस. सिंघवी, जे द्वारा सुनाया गया

1. अर्जी स्वीकृत।

2. इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका के निपटारे में 12 साल की देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त थी और खंडपीठ की खंडपीठ ने कहा गौहाटी उच्च न्यायालय ने उनके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करके गलती की।

3. अपीलकर्ता पर इस आरोप पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया गया था कि उसने 24.12.1990 को असम मोटर वर्कर्स यूनियन के सचिव राजेन दास की हत्या कर दी थी। उन्हें सत्र न्यायाधीश, कामरूप, गुवाहाटी (इसके बाद 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में संदर्भित) ने 1990 के सत्र मामले संख्या 80 (के) में दिनांक 11.11.1997 के फैसले के तहत दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

4. जब वह 1990 के सत्र मामले संख्या 80 (के) में जमानत पर था, तो कहा जाता है कि अपीलकर्ता ने हरे कांता दास (एक ट्रक मालिक) की हत्या कर दी थी। उन पर 1996 के सत्र मामले संख्या 114 (के) में मुकदमा चलाया गया था और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और इस आधार पर मौत की सजा सुनाई थी कि हत्या सबसे घृणित और वीभत्स थी।

5. अपीलकर्ता ने 1997 की अपील संख्या 254(जे) और 1998 की 2(जे) में ट्रायल कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी। दोनों अपीलों को उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.2.1998 और 12.12.1998 के फैसले के तहत खारिज कर दिया था और 1996 के सत्र वाद संख्या 114(के) में दी गई मौत की सजा की पुष्टि की गई।

6. उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को इस न्यायालय ने फैसले के तहत खारिज कर दिया था - महेंद्र नाथ दास बनाम असम राज्य (1999) 5 एससीसी 102। अपीलकर्ता के इस तर्क से निपटते समय कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की अत्यधिक सज़ा नहीं दी जानी चाहिए थी और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ कीं:

> "अब इस मामले के तथ्यों पर आते हैं, मामले की परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि हत्या बेहद वीभत्स, जघन्य, क्रूर और क्रूर थी। जिस तरह से हत्या की गई वह वीभत्स और चौंकाने वाला था. मृतक पर तलवार से वार करने के बाद जब वह गिर गया तो अपीलकर्ता ने उसका हाथ काट दिया, उसका सिर शरीर से अलग कर दिया, उसे एक हाथ में पकड़कर सड़क के माध्यम से पुलिस स्टेशन ले गया (शानदार ढंग से जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने कहा था) और दूसरे हाथ में खून टपकाने वाला हथियार. क्या यह अपीलकर्ता की अत्यधिक भ्रष्टता को नहीं दर्शाता है? हमारे विचार में ऐसा होता है।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा बताई गई कम करने वाली परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं, हालाँकि जब अपीलकर्ता ने सत्र न्यायाधीश द्वारा इस बारे में पूछताछ की गई तो उसने स्वयं कोई कम करने वाली परिस्थितियाँ नहीं बताईं, कि अपीलकर्ता 33 वर्ष का एक युवा व्यक्ति है और उसकी तीन अविवाहित बहनें हैं। और वृद्ध माता-पिता और वह उस समय ठीक नहीं थे। जब इन परिस्थितियों को विकट परिस्थितियों के विरुद्ध तौला जाता है तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि यह मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है। ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा देने में सिद्धांतों को सही ढंग से लागू किया है और उच्च न्यायालय ने इसकी पुष्टि करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

इन तथ्यों पर, मौत की सज़ा की पुष्टि करने से इनकार करना, हमारे विचार में, कानून और न्याय की राह को अवरुद्ध कर देगा। गोविंदास्वामी बनाम टीएन राज्य (1998) 4 एससीसी 531 में, मुखर्जी, जे. ने अदालत की ओर से बोलते हुए कहा, "अगर, इसके बावजूद, हम मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल देते हैं तो हम अकड़ने वाली भावना, अनियमित परोपकारिता के आगे झुक जाएंगे।" ग़लत सहानुभूति।"

7. इस न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद, अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की और मौत की सजा को

आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना की। ऐसी ही एक याचिका उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दायर की थी. असम के राज्यपाल ने दिनांक 7.4.2000 के आदेश द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दी। राष्ट्रपति को संबोधित दया याचिका जून, 2000 में असम सरकार द्वारा गृह मंत्रालय को भेज दी गई थी। राज्य सरकार के साथ बहुत सारे पत्राचार के बाद, गृह मंत्रालय ने एक नोट तैयार किया जिसमें सुझाव दिया गया कि याचिका दायर की गई थी। अपीलकर्ता को अस्वीकार किया जा सकता है। 20.6.2001 को तत्कालीन गृह मंत्री ने राष्ट्रपति से सिफारिश की कि अपीलकर्ता की दया याचिका खारिज कर दी जानी चाहिए।

8. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड यह नहीं दर्शाता है कि अगले तीन वर्षों में क्या हुआ, लेकिन अपीलकर्ता की याचिका पर सितंबर, 2004 में फिर से विचार शुरू हुआ। गृह मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर फ़ाइल पर कार्रवाई के बाद मामला गृह मंत्री की सिफारिश के साथ 19.4.2005 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता की दया याचिका खारिज कर दी जाए

9. राष्ट्रपति ने गृह मंत्री द्वारा की गई सिफारिश के आलोक में दया याचिका पर विचार किया और दिनांक 30.9.2005 को आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है:

> “मैंने महेंद्र नाथ दास के संबंध में मेरे विचार के लिए भेजे गए दया याचिका प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। मुझे लगता है

कि यद्यपि किया गया अपराध वीभत्स प्रकृति का था, फिर भी आरोपी के आचरण से पूर्व-सोच कर की गई हत्या का कोई निशान नहीं दिखता। इस अपराध के लिए उसकी ओर से मानसिक संतुलन की घोर कमी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, मेरे विचार से, उसकी दया याचिका स्वीकार कर ली जाए और उसकी मौत की सज़ा को आजीवन कारावास (अर्थात शेष जीवन के लिए) में बदल दिया जाए। जेल में आगे की कैद के दौरान, उन्हें अध्यात्मवादी और नैतिक नेताओं द्वारा समय-समय पर परामर्श दिया जा सकता है जो उनके व्यक्तित्व और मानसिक मानस को सुधारने में मदद कर सकता है। इस पर विचार किया जा सकता है.

एपीजे अब्दुल कलाम

भारत के राष्ट्रपति

30/9/2005"

10. उसी दिन, यानी 30.9.2005 को, राष्ट्रपति ने गृह मंत्री के लिए एक और नोट रिकॉर्ड किया जिसमें उन्होंने सुशील मुर्मू, संतोष यादव, मोलाई राम, महेंद्र नाथ दास, आर. गोविंदासामी, पियारा सिंह द्वारा दायर दया याचिकाओं का निपटारा किया। , सरबजीत सिंह, सतनाम सिंह और गुरदेव सिंह। उस नोट के मुताबिक, सुशील मुर्मू, संतोष यादव और मोलई राम की दया याचिका खारिज कर

दी गई. जहां तक महेंद्र नाथ दास, आर. गोविंदासामी, पियारा सिंह, सतनाम सिंह, सरबजीत सिंह और गुरदेव सिंह का संबंध है, राष्ट्रपति ने राय दी कि उनकी दया याचिकाएं स्वीकार कर ली जाएं।

11. राष्ट्रपति का नोट मिलने के बाद गृह मंत्री के कार्यालय ने अपीलकर्ता की फाइल मांगी. हालाँकि, फ़ाइल की वापसी के लिए मांग राष्ट्रपति सचिवालय को 7.9.2010 को ही भेजी गई थी। राष्ट्रपति सचिवालय ने 24.9.2010 को फाइल लौटा दी। इसके बाद, गृह मंत्रालय (न्यायिक सेल) ने लगभग 6 पृष्ठों का एक नोट तैयार किया जिसमें संबंधित अधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध का विवरण दर्ज किया, ट्रायल कोर्ट, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया और वे आधार जिन पर अपीलकर्ता ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की मांग की थी और साथ ही संघ के राष्ट्रपति सहित कुछ व्यक्तियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन और सुझाव दिया था कि दया याचिका खारिज की जा सकती है। गृह मंत्री ने इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया और सिफारिश की कि दया याचिका खारिज कर दी जा सकती है क्योंकि कोई कम करने वाली परिस्थिति नहीं थी। गृह मंत्री द्वारा 18.10.2010 को की गई सिफारिशों को राष्ट्रपति द्वारा 8.5.2011 को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद अपीलकर्ता को उसकी याचिका खारिज होने की जानकारी दी गई।

12. अपीलकर्ता द्वारा उसकी दया याचिका की अस्वीकृति पर सवाल उठाते हुए दायर की गई रिट याचिका को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसमें जगमोहन सिंह बनाम यूपी राज्य में इस न्यायालय के निर्णयों का

हवाला दिया गया था । (1973) 1 एससीसी 20, राजेंद्र प्रसाद बनाम यूपी राज्य । (1979) 3 एससीसी 464, बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 684, टीवी वाथीस्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य (1983) 2 एससीसी 68, शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 2 एससीसी 344, जावेद अहमद पावला बनाम महाराष्ट्र राज्य (1985) 1 एससीसी 275, महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य । (1987) 3 एससीसी 80, त्रिवेणीबेन बनाम गुजरात राज्य (1989) 1 एससीसी 678, मधु मेहता बनाम भारत संघ (1989) 3 एससीआर 775, सेवक पेरुमल बनाम टीएन राज्य । (1991) 3 एससीसी 471, धनंजय चटर्जी बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यूबी । (1994) 2 एससीसी 220, जशुभा भरतसिंह गोहिल बनाम गुजरात राज्य (1994) 4 एससीसी 353, रावजी बनाम राजस्थान राज्य (1996) 2 एससीसी 175, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मुन्ना चौबे (2005) 2 एससीसी 710, स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767 और देखा गया:

> "32. अब हम आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ सकते हैं कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की प्रार्थना स्वीकार की जा सकती है या नहीं। हमने पहले ही राज्य के रुख पर ध्यान दिया है कि दया याचिका पर निर्णय होने तक, याचिकाकर्ता को कभी भी निंदा कक्ष में नहीं रखा गया था जो कि सुनील बत्रा मामले में निर्धारित कानून के अनुपालन में था। उक्त रुख का किसी भी तरह से खंडन नहीं किया गया है। हालाँकि दया याचिका पर निर्णय लेने में देरी

अस्पष्ट प्रतीत होती है और यदि देरी ही एक निर्णायक कारक है, तो मौत की सजा को रद्द किया जा सकता है, लेकिन त्रिवेणीबेन में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, देरी एक ऐसा कारक है जिसके कारण मृत्युदंड रद्द किया जा सकता है। अपराध की प्रकृति और उन परिस्थितियों के साथ, जिनमें अपराध किया गया था, बाद की परिस्थितियों के प्रकाश में देखा जाना चाहिए, जैसा कि सक्षम न्यायालय ने अंतिम फैसला सुनाते समय पहले ही पाया था। इस स्तर पर, अंतिम फैसले की शुद्धता कोई मुद्दा नहीं है जैसा कि त्रिवेणीबेन (विशेषकर अनुच्छेद 22 और 76 में) में कहा गया है। देरी से परे, उस अदालत में याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव दिखाने वाली कोई अगली परिस्थिति नहीं है। पूरे समय वह अन्य कैदियों के साथ सामान्य कैदी की तरह जीवन बिताता रहा। यदि विलंब को अपराध की कायरतापूर्ण और शैतानी परिस्थितियों के साथ माना जाता है, तो याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी भी अन्य पर्यवेक्षण परिस्थितियों के अभाव में, मौत की सजा को रद्द करने का कोई मामला नहीं बनता है। इस प्रकार, जबकि देरी ने रिट याचिकाकर्ता को मौत की सजा को बदलने की मांग करने के लिए कार्रवाई का कारण प्रस्तुत किया है, किसी अन्य बाद की परिस्थितियों के अभाव में मौत की सजा को रद्द करना आवश्यक है, और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए मौत

की सजा दी गई थी, कोई आधार नहीं है इस प्रकार दी गई सज़ा को ख़त्म करने के लिए। जैसा कि शेर सिंह (पैराग्राफ 19 और 20 का अंतिम भाग) में कहा गया है, जहां तक संभव हो मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन दुर्लभ और असाधारण श्रेणी के मामलों में जहां सजा को वैध माना जाता है, उसे इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। कोई भी नियम लागू करके पराजित हो जाओ। हम पहले ही उन कारणों पर ध्यान दे चुके हैं जिनके कारण जगमोहन सिंह और बचन सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमेरिकी निर्णयों को अलग करके और भारत के विधि आयोग द्वारा अपनी 35 वीं रिपोर्ट और शर्तों में किए गए अध्ययन को ध्यान में रखते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा गया था। देश में व्याप्त है. ज्ञात हुआ कि भारत की मौजूदा स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, संसद ने मृत्युदंड को समाप्त करने के सभी प्रयासों को बार-बार खारिज कर दिया है। हमने मुन्ना चौबे मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भी उल्लेख किया है जिसमें सजा के बाद न्याय प्रणाली को नुकसान हो सकता है और कानून की प्रभावकारिता में जनता का विश्वास कम हो सकता है, सजा और अपराध में अनुपात बनाए रखने और समाज की रक्षा करने की आवश्यकता थी, पर्याप्त सज़ा आवश्यक थी. इस प्रकार, केवल देरी एक महत्वपूर्ण कारक है, यह अपने आप में मौत की

सजा को आजीवन कारावास में बदलने का आधार नहीं हो सकता है, जब अपराध और परिस्थितियां दुर्लभ से भी दुर्लभ हों, ऐसे किसी भी अन्य परिस्थिति के अभाव में इस तरह के पाठ्यक्रम को उचित ठहराया जा सकता है।

33. हमने त्रिवेणीबेन में निर्धारित कानून के सिद्धांत का विश्लेषण किया है और मौत की सजा को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया है। मधु मेहता और दया सिंह मामले में निर्णय मिसाल के तौर पर कोई और सिद्धांत नहीं देते हैं और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते प्रतीत होते हैं। हम मद्रास, राजस्थान और बंबई के उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का पालन करने के लिए भी राजी नहीं हैं कि केवल देरी ही मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए निर्णायक थी। हमारे विचार में, यह व्याख्या पहले से चर्चा किए गए कारणों से त्रिवेणीबेन में निर्धारित कानून के विपरीत है।"

13. इस मामले में दलीलें 2011 के WP (Crl.) D.No.16039, 2011 के WP (Crl.) No. 146 और 2011 के WP (Crl.) No.86 के साथ सुनी गईं, जिनका अंततः निपटारा किया गया। दिनांक 12.4.2013 को. उसमें, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान, हस्तक्षेपकर्ता (पीयूडीआर) के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केवी विश्वनाथन और विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल हरिन पी. रावल की

दलीलों पर विस्तार से गौर किया है। संक्षेप में, श्री दीवान का तर्क यह है कि भले ही अपीलकर्ता की सजा अंतिम हो गई है, लेकिन दया याचिका के निपटारे में 12 साल की देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त थी और उच्च न्यायालय ने इनकार करके गंभीर त्रुटि की है। ऐसा करने के लिए। उन्होंने विवियन रोड्रिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1971) 1 एससीसी 468, मधु मेहता बनाम भारत संघ (सुप्रा), दया सिंह बनाम भारत संघ (1991) 3 एससीसी 61 और शिवाजी जयसिंह बाबर बनाम के फैसलों पर भरोसा किया। महाराष्ट्र राज्य (1991) 4 एससीसी 375 और प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने मधु मेहता के मामले और दया सिंह के मामले में निर्णयों के अनुपात को गलत समझा और गलती से माना कि त्रिवेणीबेन के मामले में निर्धारित सिद्धांत को अपीलकर्ता के मामले काे मौत की सज़ा से आजीवन कारावास में कम करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

14. हस्तक्षेपकर्ता (पीयूडीआर) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केवी विश्वनाथन ने अपने तर्क के समर्थन में विस्तृत प्रस्तुतियाँ दीं कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के निपटान में एक दशक से अधिक की देरी मौत की सजा से आजीवन कारावास में कम करने के लिए पर्याप्त है। आजीवन कारावास में.

15. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री हरिन पी रावल ने इस बात पर जोर दिया कि अपीलकर्ता द्वारा की गई दूसरी हत्या वीभत्स और बर्बर थी और इसलिए, इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मौत की सजा को आजीवन कारावास में

बदलने का आदेश नहीं देना चाहिए। कारावास केवल इसलिए क्योंकि दया याचिका दायर करने और उसके निपटान के बीच लंबा समय था। श्री रावल ने तर्क दिया कि भले ही सितंबर, 2005 में तत्कालीन राष्ट्रपति ने राय दी थी कि अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा 8.5.2011 को लिए गए अंतिम निर्णय को देरी के आधार पर गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

16. हमने संबंधित प्रस्तुतियों पर विचार किया है। देवेंदर पाल सिंह भुल्लर के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार किया:

"(ए) संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल में निहित शक्ति की प्रकृति क्या है?

(बी) क्या संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दायर याचिका पर निर्णय लेने में देरी, अपराध की प्रकृति और परिमाण के बावजूद मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए न्यायिक आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त है । दोषी द्वारा और तथ्य यह है कि देरी देश के भीतर या बाहर से व्यक्तियों, लोगों के समूहों और संगठनों के माध्यम से दोषी द्वारा सरकार पर लाए गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दबाव या संबंधित सार्वजनिक अधिकारियों की विफलता के कारण हुई होगी। कर्तव्य?

(सी) क्या संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दायर याचिका के निपटारे में देरी के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए त्रिवेणीबेन मामले में

संविधान पीठ द्वारा निर्धारित पैरामीटर टाडा और अन्य समान कानूनों के आरोपों के तहत दोषी पाये गये व्यक्तियों पर लागू किए जा सकते हैं ?

(डी) संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा की न्यायालय की शक्ति का दायरा क्या है , जैसा भी मामला हो?"

जगमोहन सिंह के मामले, राजेंद्र प्रसाद के मामले, बचन सिंह के मामले, मारू राम बनाम भारत संघ, (1981) 1 एससीसी 107, मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) 3 एससीसी 470, एडिगा अनम्मा बनाम के फैसलों पर गौर करने के बाद। एपी राज्य (1974) 4 एससीसी 443, टीवी वाथीस्वरन का मामला, केपी मोहम्मद का मामला, शेर सिंह का मामला, जावेद अहमद का मामला, त्रिवेणीबेन का मामला, दया सिंह का मामला, ईपुरु सुधाकर बनाम एपी सरकार । (2006) 8 एससीसी 161 और अन्य न्यायक्षेत्रों के कुछ निर्णय, न्यायालय ने कहा:

"(i) संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल में निहित शक्ति राज्य के विशेषाधिकार की अभिव्यक्ति है। यह न तो अनुग्रह का मामला है और न ही विशेषाधिकार का मामला है, बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित और लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च कार्यपालिका द्वारा निर्वहन की जाने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है।

(ii) अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय , राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है। राष्ट्रपति को अपनी सलाह देते समय, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह दोषी के मामले को उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और परिमाण, समाज पर इसके प्रभाव और सभी दोषी और कम करने वाली परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट संकेत के साथ निष्पक्ष रूप से रखे। यही बात राज्य सरकार के बारे में भी सच है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल को सलाह देना आवश्यक है। सरकार की सलाह मिलने पर, जैसा भी मामला हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल को मामले में अंतिम निर्णय लेना होता है। हालाँकि, वह न्यायालय के अंतिम फैसले को पलट नहीं सकता है, लेकिन उपयुक्त मामले में, राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, मामले के रिकॉर्ड को स्कैन करने के बाद अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं कि कोई मामला है या नहीं। क्षमा, राहत आदि देने के लिए बनाया गया है। किसी भी मामले में, राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को प्रासंगिक तथ्यों का संज्ञान लेना होगा और फिर यह तय करना होगा कि क्या मामला शक्ति के प्रयोग के लिए बनाया गया है। संविधान का अनुच्छेद 72 या 161।"

उस मामले में न्यायालय ने एडिगा अनम्मा के मामले, टीवी वाथीस्वरन के मामले, केपी मोहम्मद के मामले, शेर सिंह के मामले, जावेद अहमद के मामले,

त्रिवेणीबेन के मामले, मधु मेहता के मामले, दया सिंह के मामले में की गई टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर उद्धृत किया और कहा:

> "38. उपरोक्त के प्रकाश में, अब हम याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री केटीएस तुलसी और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम जेठमलानी और श्री अंध्यारुजिना, जिन्होंने एमिकस के रूप में न्यायालय की सहायता की, के तर्क पर विचार करेंगे कि 8 साल की लंबी देरी अनुच्छेद 72 के तहत दायर याचिका का निपटारा मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए, और तो और लंबे समय तक हिरासत में रहने के कारण याचिकाकर्ता मानसिक रूप से बीमार हो गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील की दलील का जोर यह है कि दया याचिका के निपटारे में अत्यधिक देरी ने मौत की सजा को क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक बना दिया है और यह निंदा करने वाले कैदी को दी गई एक और सजा से कम नहीं है।
>
> 39. यद्यपि तर्क आकर्षक प्रतीत होता है, सभी तथ्यों पर गहराई से विचार करने पर, हम आश्वस्त हैं कि वर्तमान मामला राष्ट्रपति द्वारा सजा कम न करने के निर्णय को रद्द करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं है। याचिकाकर्ता पर लगाई गई मौत की सजा. बार-बार, (मच्छी सिंह का मामला, एडिगा अनम्मा का मामला, शेर सिंह का मामला

और त्रिवेणीबेन का मामला), यह माना गया है कि हत्या और इसी प्रकार के अपराधों के लिए सजा देते समय, न्यायालय न केवल हकदार है, बल्कि कदम उठाने के लिए बाध्य है। अपराध की प्रकृति, अपराध करने का मकसद, अपराध की भयावहता और समाज पर इसका प्रभाव, अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियार की प्रकृति आदि को ध्यान में रखें। यदि हत्या अत्यंत गंभीर तरीके से की गई है क्रूर या नृशंस तरीके से, जो समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश को जन्म देता है, अदालत को मौत की सजा देने का फैसला पूरी तरह से उचित हो सकता है। यदि पैसे या अन्य प्रकार के लालच की संतुष्टि के लिए दुल्हन को जलाकर हत्या की जाती है, तो मृत्युदंड देने का पर्याप्त औचित्य होगा। यदि अपराध की भयावहता इतनी है कि बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को बिना किसी कारण या कारण के मार दिया जाता है, तो भी, मौत की अत्यधिक सजा देना उचित होगा। संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दायर याचिका पर निर्णय लेते समय और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा शक्ति का प्रयोग करते समय, जैसा भी मामला हो, इन सभी कारकों को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए। हो सकता है, ऐसे मामलों में दया की प्रार्थना पर विचार न करना मनमाना या अनुचित नहीं माना जा सकता है

और न्यायालय केवल अनुचित देरी के आधार पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है।

40. हमारा यह भी विचार है कि शेर सिंह के मामले, त्रिवेणीबेन के मामले और कुछ अन्य निर्णयों में प्रतिपादित नियम कि लंबी देरी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के आधारों में से एक हो सकती है, उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां कोई व्यक्ति टाडा या इसी तरह के कानूनों के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है। ऐसे मामले बिल्कुल अलग स्तर पर खड़े होते हैं और इनकी तुलना व्यक्तिगत दुश्मनी या संपत्ति और व्यक्तिगत विवादों के कारण की गई हत्याओं से नहीं की जा सकती। आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई सौ निर्दोष नागरिकों और वर्दीधारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कभी-कभी, उनका उद्देश्य राजनीतिक विरोधियों सहित अपने प्रतिद्वंद्वियों का सफाया करना होता है। वे अपने विकृत राजनीतिक और अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गोलियों, बमों और सामूहिक हत्या के अन्य हथियारों का उपयोग करते हैं या राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ते हैं। ऐसा करते समय वे मानव जीवन के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते। पीड़ितों को मारने से पहले वे पीड़ितों के माता-पिता, पत्नी, बच्चों और अन्य प्रियजनों के बारे में एक

सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं। मारे गए लोगों के परिवारों को आर्थिक और अन्य नुकसान के अलावा जीवन भर पीड़ा झेलनी पड़ती है। यह विरोधाभासी है कि जो लोग दूसरों के लिए कोई दया या संवेदना नहीं दिखाते हैं वे दया की गुहार लगाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के तहत दायर याचिका के निपटारे में देरी को मौत की सजा को कम करने का आधार मानते हैं। कई अन्य लोग निर्दोष नागरिकों की भीषण हत्या और सामूहिक हत्या में शामिल आतंकवादियों के हितों का समर्थन करने और मानवाधिकारों का हौव्वा खड़ा करने के लिए बैंडबाजे में शामिल हो गए।

न्यायालय ने ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा के दायरे पर भी विचार किया और कहा:

"41. संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति या अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती की जांच करते समय, जैसा भी मामला हो, ऐसे निर्णय की न्यायिक समीक्षा की न्यायालय की शक्ति बहुत सीमित है। न्यायालय न तो अपील कर सकता है और न ही समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यदि यह पाया जाता है कि निर्णय प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दिए बिना लिया गया है या वह बाहरी या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है या किसी कारण से दूषित हो गया है तो वह

हस्तक्षेप कर सकता है। दुर्भावना या पेटेंट मनमानी के लिए - मारू राम बनाम भारत संघ , (1981) 1 एससीसी 107, केहर सिंह बनाम भारत संघ (1989) 1 एससीसी 204, स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य । (1998) 4 एससीसी 75, सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2000) 5 एससीसी 170, विकास चटर्जी बनाम भारत संघ (2004) 7 एससीसी 634, ईपुरु सुधाकर बनाम एपी सरकार । (2006) 8 एससीसी 161 और नारायण दत्त बनाम पंजाब राज्य (2011) 4 एससीसी 353।"

17. त्रिवेणीबेन के मामले में, संविधान पीठ ने टीवी वाथीस्वरन के मामले, शेर सिंह के मामले और जावेद अहमद के मामले में व्यक्त की गई परस्पर विरोधी राय पर विचार किया और कहा:

"मौत की सजा के क्रियान्वयन में अत्यधिक देरी से दोषी व्यक्ति को अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार होगा, लेकिन यह न्यायालय केवल न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सजा की पुष्टि होने के बाद हुई देरी की प्रकृति और परिस्थितियों की जांच करेगा और करेगा।" मौत की सजा को अंतिम रूप से बरकरार रखते हुए अदालत द्वारा पहुंचे निष्कर्षों को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हालाँकि, यह अदालत मामले की सभी परिस्थितियों के मद्देनजर अत्यधिक देरी के सवाल पर विचार कर सकती है ताकि यह तय किया जा सके कि

सजा का निष्पादन किया जाना चाहिए या इसे आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। मौत की सज़ा को अक्षम्य बनाने के लिए देरी की कोई निश्चित अवधि नहीं रखी जा सकती है और इस हद तक वाथीस्वरन मामले में निर्णय को सही कानून बनाने वाला नहीं कहा जा सकता है और इसलिए उस हद तक इसे खारिज कर दिया जाता है।"

18. मधु मेहता के मामले में, इस न्यायालय ने ग्यासी राम को दी गई मौत की सजा को कम कर दिया, जिसने एक सरकारी कर्मचारी, भगवान सिंह (अमीन) की हत्या कर दी थी, जिसने भू-राजस्व की बकाया वसूली के लिए उसकी संपत्ति कुर्क कर ली थी। इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील के निपटारे के बाद, दोषी की पत्नी ने 1981 में दया याचिका दायर की। यह 8 साल तक लंबित रही। इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता मधु मेहता, जो हिंदुस्तानी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक थे, द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार किया, टीवी वाथीस्वरन के मामले, शेर सिंह के मामले और त्रिवेणीबेन के मामले में निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि अत्यधिक देरी के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण के अभाव में दया याचिका के निस्तारण में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदला जाए।

19. दया सिंह के मामले के तथ्य यह थे कि याचिकाकर्ता को सरदार प्रताप सिंह कैरों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा सजा की पुष्टि की गई और विशेष अनुमति याचिका इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद

उन्होंने राज्यपाल और राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की, जिसे भी खारिज कर दिया गया। त्रिवेणीबेन के मामले के साथ उनके भाई लाल सिंह द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, उन्होंने नवंबर, 1988 में हरियाणा के राज्यपाल के समक्ष एक और दया याचिका दायर की। मामला अगले दो वर्षों तक लंबित रहा। अंत में, उन्होंने अलीपुर सेंट्रल जेल, कलकत्ता से इस न्यायालय की रजिस्ट्री को मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए एक पत्र भेजा। इस न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि याचिकाकर्ता 1972 से जेल में था और मौत की सजा के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा दी गई।

20. अपीलकर्ता के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत याचिका प्रस्तुत करने और उसकी अस्वीकृति के बीच 12 साल का लंबा अंतराल था। भारत सरकार ने केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच पत्राचार, गृह मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर मामले पर विचार आदि का हवाला देकर इस समय अंतराल को समझाने की कोशिश की है। हालांकि, समय अंतराल के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। 20.6.2001 के बीच तीन साल, यानी वह तारीख, जिस दिन तत्कालीन गृह मंत्री ने अपीलकर्ता द्वारा दायर दया याचिका को खारिज करने की सिफारिश की थी, और सितंबर, 2004, जब फाइल फिर से मंत्रालय के भीतर घूमनी शुरू हुई और 30.9.9 के बीच पांच साल .2005, यानी, वह तारीख जब राष्ट्रपति ने राय दी कि अपीलकर्ता की दया याचिका स्वीकार कर ली जाए और सितंबर, 2010, जब फाइल वास्तव में गृह मंत्रालय द्वारा वापस बुलाई गई थी। इसके अलावा, सबसे दिलचस्प बात यह है कि गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा तैयार दिनांक

5.10.2010 के नोट में, बनाते समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के दिनांक 30.9.2005 के नोट का संदर्भ दिया गया था। 12.10.2010 को राष्ट्रपति के कार्यालय में उत्तराधिकारी को अपीलकर्ता की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश, गृह मंत्री ने 30.9.2005 के नोट का उल्लेख भी नहीं किया। राष्ट्रपति के विचारार्थ गृह मंत्रालय द्वारा तैयार सारांश, जिस पर गृह मंत्री ने 18.10.2010 को हस्ताक्षर किये थे, में भी तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश एवं नोट दिनांक 30.9.2005 का कोई संदर्भ नहीं दिया गया। ऐसा क्यों किया गया यह उत्तरदाताओं द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। हालाँकि, अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका और उसमें दर्ज विभिन्न नोट्स वाली फ़ाइल राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई होगी, लेकिन उनके विचार के लिए तैयार किए गए सारांश से उनके पूर्ववर्ती द्वारा पारित आदेश और दिनांक 30.9.2005 के नोट का उल्लेख नहीं किया गया है। इस निष्कर्ष पर कि राष्ट्रपति को उनके पूर्ववर्ती द्वारा व्यक्त किए गए विचार के बारे में अंधेरे में रखा गया और पूरे मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार करने के अवसर से वंचित किया गया।

21. यह न तो प्रतिवादियों का अभिवचनित मामला है और न ही इस न्यायालय के समक्ष यह दर्शाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत की गई है कि भारत सरकार ने 30.9.2005 को उनके द्वारा दर्ज आदेश की समीक्षा के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के समक्ष फाइल रखी थी। जिसने अंततः 8.5.2011 को अपीलकर्ता की याचिका पर निर्णय लिया, उससे अपने पूर्ववर्ती के निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि

अपीलकर्ता द्वारा दायर याचिका के निपटान में राष्ट्रपति को उचित सलाह और सहायता नहीं दी गई थी।

22. गौहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ को गृह मंत्रालय द्वारा रखे गए रिकॉर्ड/फ़ाइलों को देखने का लाभ नहीं मिला और यही कारण है कि विवादित आदेश में राष्ट्रपति द्वारा पारित आदेश का कोई संदर्भ नहीं है। 30.9.2005 को और गृह मंत्री के विचारार्थ उनके द्वारा दर्ज किया गया नोट।

23. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, हम आश्वस्त हैं कि अपीलकर्ता की दया याचिका के निपटान में 12 साल की देरी मौत की सजा को कम करने के लिए पर्याप्त थी और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने केवल रिट याचिका को खारिज करके गंभीर त्रुटि की। इस आधार पर कि उसे जघन्य अपराध करने का दोषी पाया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दया सिंह के मामले में फैसले को इस धारणा पर अलग करना भी उचित नहीं था कि ऐसा प्रतीत होता है कि मामला संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा तय किया गया है । उस फैसले को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि इस अदालत ने मौत की सजा के क्रियान्वयन में 12 साल के लंबे अंतराल और त्रिवेणीबेन के मामले में संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए दया सिंह की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था। यह निर्णय के पैराग्राफ 5, 7, 8 और 9 से स्पष्ट होता है, जो नीचे दिए गए हैं:

> “5. आगे बढ़ने से पहले हम त्रिवेनिबेन मामले में उस निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं जो उस सिद्धांत को बताता है जो वर्तमान

याचिका को नियंत्रित करता है। हालाँकि मामले दो निर्णयों द्वारा निपटाए गए, पीठ की राय के अनुसार, जो सर्वसम्मत था, मौत की सजा के निष्पादन में अनुचित देरी से दोषी कैदी को अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार मिलता है, लेकिन यह न्यायालय केवल मामले की जांच करेगा । न्यायिक प्रक्रिया द्वारा सजा की अंततः पुष्टि किए जाने के बाद हुई देरी की प्रकृति और उत्पन्न परिस्थितियाँ, और अंततः मौत की सजा को बरकरार रखते हुए अदालत द्वारा पहुंचे निष्कर्षों को फिर से खोलने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। इसके अलावा, अत्यधिक देरी की शिकायत पर विचार करते समय यह न्यायालय यह तय करने के लिए मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार कर सकता है कि क्या मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए, और सजा देने के लिए देरी की कोई निश्चित अवधि नहीं रखी जा सकती है। मृत्यु अक्षम्य. इन टिप्पणियों के आलोक में वर्तमान मामले की परिस्थितियों की जांच की जानी है।

7. आगे की देरी का प्रारंभिक कारण याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक नई दया याचिका है। क्या यह तथ्य उसे दो साल से अधिक समय तक प्रत्याशा की भावना में रखने को उचित ठहराता है? यदि प्रार्थना को तुरंत खारिज करने लायक नहीं समझा गया तो फांसी पर रोक लगाना निश्चित रूप से उचित था, लेकिन मामले को

शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए था और इसे स्थगित नहीं रखा जाना चाहिए था जैसा कि किया गया है। भारत संघ की ओर से दायर जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि अंतिम दया याचिका की प्राप्ति पर हरियाणा के राज्यपाल ने तुरंत भारत के राष्ट्रपति को एक संदर्भ दिया और इस सवाल पर ज्ञान मांगा कि क्या राज्यपाल, इस तरह से निपटते समय आवेदन, राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से बाध्य है और क्या राज्यपाल ऐसे मामले में अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है, जहां इसी आशय का एक पूर्व आवेदन राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस संचार की प्राप्ति के तुरंत बाद, मामले को सलाह के लिए कानूनी मामलों के विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय को भेजा गया था, और मंत्रालय ने सुझाव दिया कि इस प्रश्न पर भारत के अटॉर्नी जनरल के साथ चर्चा की जानी चाहिए। चूँकि मामला विचाराधीन रहा, इसलिए प्रश्न का कोई उत्तर नहीं भेजा जा सका और अंततः इस वर्ष मार्च में ही, सभी मुख्य सचिवों को संविधान के अनुच्छेद 257(1) के तहत एक निर्देश के रूप में उत्तर भेजा जा सका। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की. हालाँकि, हलफनामा देरी के औचित्य में कोई तथ्य या परिस्थिति प्रस्तुत नहीं करता है। उत्तरदाताओं द्वारा किसी भी उचित स्पष्टीकरण के अभाव में हमारा विचार है कि यदि संबंधित अधिकारियों ने मामले

पर आवश्यक ध्यान दिया होता और इसकी तात्कालिकता के लिए आवश्यक समय समर्पित किया होता, तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि संदर्भित प्रश्नों पर विचार करने की पूरी प्रक्रिया सफल होगी। बिना किसी अंतराल के उचित अवधि के भीतर पूरा कर लिया गया है, जिसे विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने "शर्मनाक अंतर" के रूप में वर्णित किया है। इस प्रकार, एक टालने योग्य देरी हुई है, जो वर्तमान मामले में परिस्थितियों की समग्रता में काफी है, जिसके लिए निंदा करने वाला कैदी किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है।

8. जैसा कि त्रिवेणीबेन मामले में इस न्यायालय द्वारा आगाह किया गया था, हम सामान्य आवेदन का कोई नियम नहीं बना रहे हैं कि दो साल की देरी से मौत की सजा पाए दोषी को उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार मिल जाएगा, बल्कि हम ऐसा कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचार करने के लिए मामले की सभी परिस्थितियों के संचयी प्रभाव को ध्यान में रखा गया। यद्यपि इस तथ्य को कि याचिकाकर्ता को 1972 से लगातार जेल में हिरासत में रखा गया है, उसकी पिछली रिट याचिका को खारिज करते समय ध्यान में रखा गया था, इसे वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं बनाया गया है और हमने इसे केवल एक परिस्थिति के रूप में

ध्यान में रखा है। अक्टूबर 1988 में दिए गए फैसले के बाद उत्पन्न हुई प्रासंगिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप महत्व मानते हुए।

9. मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम याचिकाकर्ता की मौत की सजा के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा देना उचित समझते हैं। तद्नुसार रिट याचिका स्वीकार की जाती है।"

24. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है, आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाता है। अपीलकर्ता की दया याचिका की अस्वीकृति को अवैध घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा उसे मौत की सजा दी जाती है, जिसकी पुष्टि उच्च न्यायालय ने की है और इस न्यायालय ने इसे आजीवन कारावास में बदल दिया है।

बी.बी.बी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टू "सुवास" की सहायता से न्यायिक अधिकारी सुप्रिया जोशी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****